look at the Budget, the Finance Minister, knowing that the Government of Idnia require Rs. 38,600 crores to implement this all over the country, announced this scheme only for 170 districts. Even to implement in these districts, it requires Rs. 8,984 crores, but the Government of India allocated only Rs. 1311.05 crores. There is no provision about additional allocation required. The Bill excluded even urban slum-dwellers and lower-middle class! You are not giving employment to all rural people; you are giving only to people who are identified by the Government. The NCMP says that the Government of India would provide funds, whereas the Bill says that States would provide funds. The Bill is silent if States fail to pay unemployment allowance. These are all measures to suppress the right to work promised under the NCMP. Hence, I request that a Group of Ministers should look into all these aspects and bring a revised Bill depicting all the issues mentioned to make the dream of the NCMP -- of giving employment to all -- a reality.

Demands to maintain the *status quo* for use of common salt in the country

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीयों को अपना नमक खुद बनाने का अधिकार दिलवाने हेतु महात्मा गाँधी ने दांडी यात्रा की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस यात्रा के स्मरण में कार्यक्रम करने वाली पार्टी की अगुवाई में चलने वाली सरकार साधारण नमक पर पाबन्दी लगाने जा रही है। सेहत के नाम पर आम आदमी से नमक बनाने का अधिकार छीनने की तैयारी हो रही है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता दिवस से ही देश में साधारण नमक की बिक्री पर पूर्ण निषेधादेश लागू किया जा रहा है। आयोडीन रहित नमक पर प्रतिबन्ध लगाने के पीछे सरकार का तर्क है कि आयोडीन की कमी के कारण शरीर में कई प्रकार के विकार आ जाते हैं। परन्तु चिकित्साविदों का कहना है कि आयोडीनयुक्त नमक की आवश्यकता केवल उन्हीं इलाकों में है, जहाँ आयोडीन का अभाव है। जिन लोगों को अतिरिक्त आयोडीन की जरूरत नहीं है, नमक के जरिए उनके शरीर में अधिक आयोडीन पहुँचने से भी प्रतिकूल असर हो सकता है। एक महत्वपूर्ण विषय और भी है कि खाना पकाने के समय आयोडाइज्ड सॉल्ट डाले जाने से वह उत्ताप के कारण उड़ जाता है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रहता है। 'टेबल सॉल्ट' की दृष्टि से आयोडाइज्ड सॉल्ट का सीमित व्यवहार हो सकता है। लेकिन इसके लिएं नमक बनाने का काम बड़ी कम्पनियों को मिल जाएगा और कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा, इसका भय भी है। जिसे आयोडीनयुक्त नमक जितना आवश्यक हो, वे उतना व्यवहार करें। मात्र आयोडीन अभाव के तर्क पर साधारण नमक का सम्पूर्ण निषेध अनुचित और

अन्याय है। अत: मैं आपके माध्यम से यह माँग करता हूँ कि पहले की तरह देश में साधारण नमक का प्रचलन चलता रहे और आयोडाइज्ड सॉल्ट को बाध्यतापूर्ण, 'कंपलसरी' न किया जाए।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Shri S.S. Chandran; not present.

Demand to prevail upon government of Maharashtra to adhere to 15 percent reservation for SCs.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, keeping in view the spirit of the Constitution of India, the Government of India prescribed 15 per cent reservation at the national level for Scheduled Castes in initial recruitment in Government services, school and college admissions, and other allied matters.

The Maharashtra Government had earlier fixed 13 per cent reservation for Scheduled Castes. But contrary to this, and contrary to the spirit of the Constitution and the policy of the Government of India, the Maharashtra Government in its recently passed decision, further reduced the reservation from 13 per cent to 8 per cent in the districts of Thane, Dhule, Nandurbar, Nasik, Yeotmal and Raigad in Maharashtra. This is contrary to the spirit of the Constitution and the policy adopted by the Government of India, and thereby great injustice is done towards the Scheduled Castes in the said districts.

I request the hon. Home Minister of India to take up this matter with the Maharashtra Government for not violating the spirit of the Constitution and the policy of the Government of India.